ब्रहस्पतिवार, 16 अप्रैल, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

रोहित मुंबई के अगले दो मैच मिस कर सकते हैं

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक रिलीज

Page-05

**विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन विधेयक पेश करने के तरीके और परिसीमन पर आपत्ति जताई।मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार बिना जनगणना के राजनीतिक लाभ के लिए कदम उठा रही है।इस मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सियासी टकराव तेज होने के संकेत हैं।**

# महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम! समर्थन के बावजूद विपक्ष क्यों कर रहा विरोध?

- **मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन परिसीमन और विधेयक लाने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई।**

- **विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार जनगणना और निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना राजनीतिक लाभ के लिए बदलाव कर रही है।**

विपक्ष की अहम बैठक के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए साफ किया कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा विधेयक पेश करने के तरीके पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है।इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन इसके साथ जो शर्तें जोड़ी गई हैं, खासकर परिसीमन, वह चिंता का विषय है। उनका कहना है कि सरकार पहले जनगणना कराए बिना और पुराने संशोधनों को लागू किए बिना इस विधेयक को आगे बढ़ा रही है, जो संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को कमजोर कर कार्यपालिका के हाथों में ज्यादा नियंत्रण देने की कोशिश कर रही है।वहीं आईयूएमएल सांसद ई. टी. मोहम्मद बशीर ने भी परिसीमन को "जाल" बताते हुए कहा कि सरकार चाहे तो पहले ही महिलाओं को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ना एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए संसद को जनसंख्या निर्धारण और परिसीमन का व्यापक अधिकार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, इससे साधारण बहुमत के आधार पर सरकार पूरे देश की राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी।इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है।

## विजय का बड़ा हमला, केंद्र पर भेदभाव का आरोप

विजय ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे "भेदभावपूर्ण कार्रवाई" बताया है। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा और दक्षिण के राज्यों की आवाज कमजोर हो सकती है।।5 अप्रैल को दिए गए बयान में विजय ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान का स्वागत किया और स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि इस विधेयक के लागू होने के बाद दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से कम हो सकता है।विजय ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ, तो भाषा, संस्कृति, राज्य के अधिकारों और केंद्र की नीतियों से जुड़े अहम फैसलों में दक्षिण भारत की भागीदारी घट जाएगी। उनके अनुसार, इससे उत्तर भारत के राज्यों का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों की आवाज संसद में कमजोर पड़ सकती है, जो अब तक केंद्र की नीतियों का पालन करते रहे हैं।विजय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने निर्देशों का पालन करने वाले राज्यों को "दंड" और उल्लंघन करने वालों को "पुरस्कार" दे रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उसी दिशा में एक संकेत देता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ सकता है।

## पी. चिदंबरम बोले- 850 सीटों का खेल एक भ्रम

पी चिदंबरम ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोयंबटूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को "भ्रम और धोखा" करार दिया और निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया की मांग की। उन्होंने तीन दिवसीय विशेष संसद सत्र के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति हो सकती है।चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावों के चलते कई विपक्षी सांसद संसद में मौजूद नहीं रह पाएंगे, जिसका फायदा उठाकर सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अचानक संसद बुलाई जाती है, तो विपक्ष को प्रस्ताव के प्रावधानों को समझने का भी समय नहीं मिलेगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया चाहते हैं।

# बिहार में सत्ता का बड़ा फेरबदल! मंत्रियों के बंटवारे ने बढ़ाई सियासी हलचल

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और सम्राट चौधरी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब एनडीए गठबंधन के भीतर मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिससे सत्ता संतुलन की नई झलक सामने आई है।सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में अलग-अलग दलों के प्रतिनिधित्व को लेकर सहमति बन गई है। भाजपा को मुख्यमंत्री पद सहित कुल 15 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू को दो उपमुख्यमंत्रियों समेत 17 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसके अलावा एलजेपी (राम विलास) को 2 मंत्री, एचएम को 1 और आरएलएम को 1 मंत्री पद मिलने की बात सामने आई है।नई सरकार में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र कुमार यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास कुल 29 विभागों का प्रभार रखा है, जो उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। वहीं विजय चौधरी को 10 विभाग और बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार 1 मई को होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद एनडीए सहयोगियों के बीच तालमेल बनाए रखना आसान नहीं होगा। साथ ही, सम्राट चौधरी के सामने जेडीयू के भीतर संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी, खासकर उस वक्त जब इस्तीफे के बाद पार्टी में अंदरूनी असंतोष की चर्चाएं सामने आई थीं।हालांकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

| साईज | विजिटिंग कार्ड | क्वाटर पेज | हाफ पेज | फुल पेज (अंदर) | फुल पेज (कवर 2 - 3) | फुल पेज (कवर 4 - अंतिम) | (फ्रंट पेज) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेट | ₹ 3000 | ₹ 6000 | ₹ 10,000 | ₹ 20,000 | ₹ 25,000 | ₹ 30,000 | ₹ 100000 |

8601780000

## मजदूर लौटे काम पर नोएडा में बवाल के बाद हालात काबू में

गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जारी फैक्ट्री श्रमिकों का हिंसक विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह शांत हो गया है। प्रशासन और सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। लक्ष्मी सिंह ने पुष्टि की है कि श्रमिकों की प्रमुख मांगें मान ली गई हैं और अब अधिकांश कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं।इंडिया टीवी से बातचीत में लक्ष्मी सिंह ने बताया कि समय रहते उठाए गए कदमों के चलते हालात बिगड़ने से बच गए। कंपनियों ने मजदूरों की कई अहम मांगों को स्वीकार किया है, जिनमें वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करना और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों के समाधान के लिए समितियों का गठन शामिल है। फैक्ट्रियों के बाहर संशोधित वेतन से जुड़े नोटिस भी लगाए गए हैं, जिससे श्रमिकों का भरोसा फिर से कायम हुआ है।पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त जारी है। अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पहचान की है, जिन पर श्रमिकों को भड़काने और माहौल खराब करने के आरोप हैं।कमिश्नर ने यह भी खुलासा किया कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग संबंधित फैक्ट्रियों के नियमित कर्मचारी नहीं थे, जबकि कुछ हाल ही में जुड़े थे और उन पर विरोध को उकसाने में भूमिका निभाने का शक है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

# नारी शक्ति कानून पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का समर्थन, पीएम मोदी की पहल की सराहना

**पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण कानून का समर्थन किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम बताया। सरकार संसद में इसे लागू करने की तैयारी में है, जबकि भाजपा ने व्हिप जारी किया है। यह कानून महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है।**

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने इस कानून को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया।अपने पत्र में प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह संवैधानिक संशोधन विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने लिखा कि यह कदम देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।पूर्व राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण और समान अवसरों की वकालत की है। उन्होंने इस दिशा में योगदान देने वाले सभी हितधारकों की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि यह कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा।वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अधिनियम को लागू करने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 'नारी शक्ति' के नाम एक पत्र लिखकर इस बहुप्रतीक्षित विधेयक के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है और इससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा।संसद के आगामी सत्र को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस अधिनियम के समर्थन का आग्रह किया है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सरकार इस कानून से जुड़े संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सांसदों को तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह संकेत है कि सरकार इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है।गौरतलब है कि सितंबर 2023 में पारित इस कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है। इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक संतुलित और प्रतिनिधिक बनाएगा।

## संवैधानिक ढांचे में बड़ा बदलाव

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

संसद में पेश किए जाने वाले नए विधायी प्रस्तावों के तहत जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक और राजनीतिक संरचना में व्यापक बदलाव की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026, संघ शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 और संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन और प्रतिनिधित्व को नई रूपरेखा देने की तैयारी है। परिसीमन विधेयक 2026 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के क्षेत्रों के मुक्त होने पर चुनाव आयोग को वहां निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का अधिकार मिलेगा। यह प्रावधान भारत के उस रुख को मजबूत करता है कि पूरा जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं, जबकि PoJK की 24 सीटें रिक्त रखी जाती हैं और कुल संख्या में शामिल नहीं होतीं। संघ शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 के तहत परिसीमन आयोग को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या तय करने का अधिकार दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, यह संख्या 114 सीटों से कम नहीं होगी। इससे पहले के प्रावधानों में PoJK को परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, जिसे अब बदलने की तैयारी है। विधेयक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। वर्तमान में उपराज्यपाल को दो महिलाओं को नामित करने का अधिकार है, जिसे बढ़ाकर तीन करने की योजना है। हालांकि यह बदलाव नए परिसीमन के बाद ही लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत जनसंख्या की परिभाषा, सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन संसद द्वारा तय जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

# भारत 2035 तक बनाएगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और अब भारत भी इस दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2035 तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत ने रूस के साथ सहयोग की इच्छा जताई है, जिससे दोनों देशों के अंतरिक्ष संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक स्वदेशी कक्षीय प्रयोगशाला होगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति सुनिश्चित करना, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आधार तैयार करना है। इस परियोजना के तहत पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक लॉन्च करने की योजना है, जबकि पूरा स्टेशन 2035 तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया

जाएगा। इसे पांच मॉड्यूलों में विकसित किया जाएगा, जहां तीन से चार अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से रह सकेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर छह सदस्य अल्प अवधि के लिए ठहर सकेंगे। इस तरह यह स्टेशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रूस के साथ सहयोग को इस परियोजना के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस को अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण और संचालन का लंबा अनुभव है। 'मीर' अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उसकी भूमिका उसकी तकनीकी दक्षता को दर्शाती है।

# चीन का बड़ा बयान

## ईरान को सैन्य मदद के आरोप सिरे से खारिज

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

चीन ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि वह ईरान को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। यह बयान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की सभी रिपोर्टें "पूरी तरह मनगढ़ंत" हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। यह विवाद उस समय बढ़ा जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए "TEE-01B" नामक एक चीनी उपग्रह हासिल किया है। हालांकि, चीन ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी प्रकार की सैन्य संलिप्तता से साफ इनकार किया। हालांकि अपने बयान में चीन ने किसी विशेष रिपोर्ट का नाम नहीं लिया।इन आरोपों को खारिज करने के साथ ही बीजिंग ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी। लिन जियान ने कहा कि यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाता है, तो चीन भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव और बढ़ सकता है। इस बीच, क्षेत्रीय हालात भी तेजी से बदल रहे हैं। इस्लामाबाद में शांति

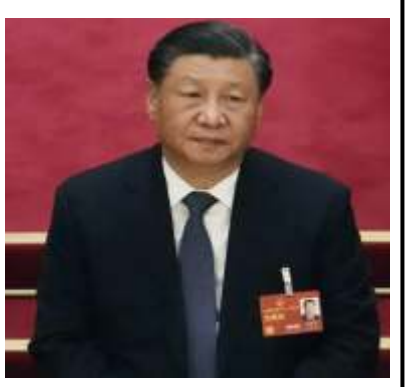

वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चीन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि चीन युद्धविराम के दौरान ईरान को हथियारों की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में है। मौजूदा घटनाक्रम से यह साफ है कि ईरान, अमेरिका और चीन के बीच तनाव और गहरा सकता है, जिसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

# ईरान पर दबाव का कोई असर नहीं होगा

## शांति चाहते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं: मसूद पेज़ेश्कियन

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मसूद पेज़ेश्कियन ने बुधवार को ईरान के खिलाफ बढ़ते बाहरी दबाव और सैन्य कार्रवाइयों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लामी गणराज्य पर बल प्रयोग करने की किसी भी कोशिश का अंततः विफल होना तय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान शांति और संवाद का समर्थक है, लेकिन किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। पेज़ेश्कियन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और युद्धविराम को लेकर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान रचनात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसकी संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि "हम बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन किसी भी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे।" सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर जल्द हो सकता है, क्योंकि पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में

बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच संवाद की संभावना बनी हुई है।पेज़ेश्कियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि देश पर अपनी शर्तें थोपने या उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की किसी भी कोशिश को ईरानी जनता स्वीकार नहीं करेगी।उन्होंने हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। आरोप है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस संदर्भ में पेज़ेश्कियन ने इजरायल और अमेरिका की कार्रवाइयों की वैधता और नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न उठाए।

## संपादक की कलम से

देश में लगातार बढ़ती महंगाई आज आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं—जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन और बिजली—की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने आम आदमी के बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर चलाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। महंगाई का सीधा असर लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ता है। जब आय सीमित हो और खर्च बढ़ता जाए, तो लोगों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। इसका असर न केवल उनके जीवन स्तर पर पड़ता है, बल्कि समग्र आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। जब लोग कम खर्च करते हैं, तो बाजार में मांग घटती है और इससे आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, मौसम की मार से फसलों को नुकसान और घरेलू स्तर पर करों का बोझ—ये सभी कारक मिलकर कीमतों को बढ़ाते हैं। हाल के समय में वैश्विक परिस्थितियों ने भी इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। सरकार और केंद्रीय बैंक इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर कदम उठाते हैं, जैसे ब्याज दरों में बदलाव, सब्सिडी या करों में राहत। हालांकि, इन उपायों का असर तुरंत नहीं दिखता और आम जनता को लंबे समय तक दबाव झेलना पड़ता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नीतियां केवल अल्पकालिक राहत तक सीमित न रहें, बल्कि दीर्घकालिक समाधान पर भी ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था और प्रभावी निगरानी से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। कृषि क्षेत्र में सुधार और भंडारण सुविधाओं के विकास से भी खाद्य महंगाई को कम किया जा सकता है। अंततः, महंगाई केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ विषय है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार, उद्योग और समाज सभी मिलकर इस चुनौती का समाधान खोजें, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और अर्थव्यवस्था संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके।

## केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दायर किया

# जज को हटाने की मांग दोहराई

**दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दायर कर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग दोहराई। उन्होंने जज के परिवार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच संबंधों को हितों का टकराव बताते हुए निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठाए।**

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति (एक्साइज पॉलिसी) से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की अपनी मांग एक बार फिर दोहराई है। इस नए हलफनामे ने मामले को एक नया कानूनी मोड़ दे दिया है और न्यायिक निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दी है।यह पूरा मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ में चल रही है। केजरीवाल ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि इस मामले में हितों के टकराव (Conflict of Interest) की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। हलफनामे के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में वकील के रूप में कार्यरत हैं। केजरीवाल ने बताया कि उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप 'ए' वकीलों की सूची में शामिल है, जबकि उनकी बेटी ग्रुप 'सी' वकील के रूप में सूचीबद्ध हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में भी केंद्र सरकार की ओर से पेश होती हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इन वकीलों को मामले आवंटित करने की प्रक्रिया में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भूमिका होती है। खास बात यह है कि तुषार मेहता ही इस मामले में सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हो रहे हैं और केजरीवाल की उस याचिका का विरोध कर रहे हैं जिसमें न्यायमूर्ति को मामले से अलग करने की मांग की गई है। अपने हलफनामे में केजरीवाल ने कहा है कि यह स्थिति "प्रत्यक्ष और गंभीर पक्षपात की आशंका" पैदा करती है। उनका तर्क है कि जब वही विधि अधिकारी और संस्थागत ढांचा, जो न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों को सरकारी कार्य आवंटित करता है, उसी मामले में एक पक्ष के रूप में अदालत में उपस्थित हो, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।उन्होंने अदालत से अपील की है कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपी जाए। उनका कहना है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा पहले ही इस मामले से जुड़े आवेदनों पर अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी हैं। ऐसे में केजरीवाल द्वारा दाखिल यह नया हलफनामा अदालत के निर्णय को प्रभावित कर सकता है या कम से कम इस मुद्दे पर विस्तृत विचार की आवश्यकता पैदा कर सकता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि हितों के टकराव से जुड़े मामलों में अदालतें बेहद सतर्क रहती हैं, क्योंकि न्यायपालिका की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाती है। अब देखना होगा कि अदालत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है। फिलहाल, यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से काफी अहम बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

# सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर रोक

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी से बचाव के लिए दी गई अंतरिम राहत पर रोक लगा दी है। यह राहत पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई थी। मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि रिनिकी भुयान सरमा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं। उन्होंने दावा किया कि इन तथ्यों का खुलासा मुख्यमंत्री द्वारा 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों ने असम की राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि, सरमा परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। इसके बाद गुवाहाटी के अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, जिनमें चुनाव से संबंधित झूठे बयान (धारा 175), आत्मरक्षा से जुड़ी धारा 35 और धोखाधड़ी (धारा 318) शामिल हैं। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पवन खेड़ा ने 7 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया और हैदराबाद का अपना आवासीय पता दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग की। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी, ताकि वे आगे उचित अदालत में राहत के लिए अपील कर सकें।लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम राहत पर रोक लगा दी है, जिससे खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल, सभी की नजरें इस केस की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो आगे की दिशा तय करेगी।

# राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा वापस

## AAP में अंदरूनी कलह

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की Z+ श्रेणी की सुरक्षा पंजाब पुलिस द्वारा वापस ले ली गई है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, अब उनके लिए केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के मुताबिक, पंजाब से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए राघव चड्ढा को राज्य सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, पिछले सप्ताह यह सुरक्षा अचानक वापस ले ली गई। इसके बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिलहाल दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा नई सुरक्षा व्यवस्था की औपचारिक पुष्टि नहीं हो जाती। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आम आदमी पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हाल ही में पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटा दिया था। इस फैसले के बाद चड्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें "खामोश किया गया है, हारा नहीं।" पार्टी के कुछ नेताओं ने चड्ढा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया और केंद्र सरकार के खिलाफ अपेक्षित आक्रामक रुख नहीं अपनाया। इसके बजाय उन पर जनसंपर्क गतिविधियों में अधिक ध्यान देने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, चड्ढा ने इन सभी आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने AAP की पंजाब इकाई में चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। सुरक्षा में बदलाव और संगठनात्मक फैसले आपस में जुड़े हो सकते हैं, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि इसी दौरान पार्टी के एक अन्य सांसद अशोक मित्तल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी भी हुई थी, जिससे पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल, पंजाब पुलिस या केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा हटाने के पीछे के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक और सुरक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बना हुआ है।

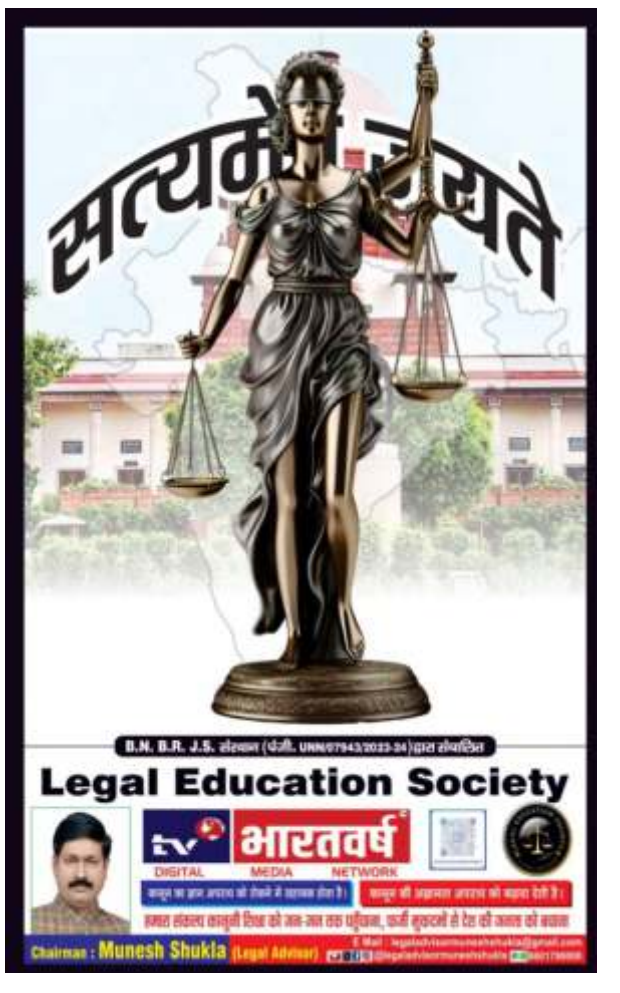

# 2026 में थोक महंगाई बढ़कर 3.88%
# अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक संकेत सामने आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 3.88 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि फरवरी 2026 में यह दर मात्र 2.13 प्रतिशत थी। एक महीने में आई यह तेज बढ़ोतरी औद्योगिक लागत, उत्पादन कीमतों और आम जनता पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष बोझ को लेकर नई बहस को जन्म दे रही है। मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि थोक महंगाई में यह वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य विनिर्माण उत्पादों, गैर-खाद्य वस्तुओं, बुनियादी धातुओं और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आए उछाल के कारण दर्ज की गई है।आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं (भार 22.62 प्रतिशत) में 6.36 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई है। इसमें महीने-दर-महीने 2.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसका प्रमुख कारण कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेजी है। यह संकेत देता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता का सीधा असर घरेलू थोक बाजार पर पड़ रहा है। इसी तरह, ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत) की दर भी नकारात्मक क्षेत्र से निकलकर सकारात्मक हो गई है और 1.05 प्रतिशत दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भू-राजनीतिक तनावों के कारण ऊर्जा कीमतों में आए उछाल को दर्शाता है, जिसका असर उत्पादन लागत और परिवहन खर्चों पर भी पड़ सकता है। विनिर्मित उत्पादों (भार 64.23 प्रतिशत) के क्षेत्र में भी महंगाई 3.39 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि औद्योगिक सेक्टर में लागत का दबाव लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इस श्रेणी के 22 समूहों में से 16 समूहों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो व्यापक स्तर पर मूल्य दबाव को दर्शाता है। वित्तीय WPI में यह बढ़ोतरी आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई (CPI) पर भी असर डाल सकती है। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है और इसका प्रभाव वस्तुओं की अंतिम कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इस बीच, PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा कि मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 में WPI महंगाई में आई यह तेज वृद्धि कीमतों की व्यापक मजबूती को दर्शाती है। उनके अनुसार, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऊर्जा आधारित उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं में आई तेजी तथा प्राथमिक वस्तुओं में पहले आई नरमी के उलटाव के कारण हुई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों के खाद्य घटक शामिल होते हैं, फरवरी 2026 के 192.9 स्तर से घटकर मार्च 2026 में 192.8 पर आ गया है। यह दर्शाता है कि खाद्य कीमतों में मामूली स्थिरता बनी हुई है, हालांकि कुल महंगाई में अन्य क्षेत्रों की भूमिका अधिक रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह रुझान जारी रहता है तो यह आर्थिक स्थिरता, निवेश लागत और उपभोक्ता बाजार पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

## बार्सिलोना की जीत बेकार, एटलेटिको मैड्रिड सेमीफाइनल में पहुंचा

चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराया, लेकिन कुल स्कोर 3-2 रहने से टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पहले लेग में एटलेटिको ने 2-0 की जीत हासिल की थी, जो आखिर में निर्णायक साबित हुई। इस जीत की बदौलत वह एग्रीगेट स्कोर पर 3-2 से आगे रही। एटलेटिको मैड्रिड 2017 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। अब अगले दौर में उनका मुकाबला आर्सेनल या स्पोर्टिंग लिस्बन में से किसी एक से होगा। मैच के शुरुआती 24 मिनटों में ही बार्सिलोना ने दो गोल कर बढ़त बना ली थी। चौथे मिनट में ही युवा खिलाड़ी लेमिन यमल ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। उन्होंने एटलेटिको के डिफेंडर क्लेमेंट लेंगलेट की गलती का फायदा उठाया। इसके बाद 24वें मिनट में फेरान टॉरेस ने दानी ओल्मो के पास पर गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने हार नहीं मानी और मैच में वापसी की। मैच का सबसे अहम मोड़ 31वें मिनट में आया। मार्कोस लोरेंटे के पास पर एडमोला लुकमैन ने एटलेटिको के लिए गोल किया। यह गोल एग्रीगेट स्कोर के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। दूसरे हाफ में बार्सिलोना ने एक और गोल किया, लेकिन फेरान टोरेस का यह गोल ऑफसाइड करार दे दिया गया। गोलकीपर जोन गार्सिया ने भी एक अहम बचाव किया। मैच के दौरान गावी और माटेओ रुगिएरी के बीच टक्कर में रुगिएरी को चोट लगी और खेल कुछ देर रुका।

# रोहित मुंबई के अगले दो मैच मिस कर सकते हैं

## धोनी का असर जारी, नूर अहमद के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव

महेंद्र सिंह धोनी भले ही चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वर्तमान सत्र में अभी तक नहीं खेल पाए हैं लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के प्रदर्शन में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है जिसकी एक बानगी स्पिनर नूर अहमद के कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच विजेता प्रदर्शन में देखने को मिली। अफगानिस्तान के बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर नूर इस मैच से पहले तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और उन्होंने चार मैचों में केवल एक विकेट लिया था। लेकिन नेट पर अभ्यास के दौरान धोनी से लंबी बातचीत के बाद उनके खेल में बदलाव देखने को मिला। उन्होंने केकेआर के खिलाफ चार ओवरों में 21 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने बीच के ओवरों में अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन के विकेट लेकर सीएसके की 32 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई। पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन नूर बल्लेबाजों पर हावी होने में कामयाब रहे। सीएसके के सहायक कोच श्रीधरन श्रीराम ने नूर की मैच से पहले धोनी के साथ हुई बातचीत के बारे में बात की। धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पा रहे हैं। श्रीराम ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी। आज उसकी गेंद की गति हवा में थोड़ी धीमी थी। गेंद पर साइड स्पिन ज्यादा थी और ड्रॉप भी ज्यादा था। इस पर वह काम कर रहा है।" उन्होंने कहा, "धोनी ने अभ्यास सत्र के दौरान उनसे काफी देर तक बात की और उन्हें लेग अधिक ब्रेक करने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगता है कि आज उससे मदद मिली और इसके परिणाम सबके सामने हैं।" श्रीराम ने वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन और नूर के संयोजन पर भी बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे से संवाद भी करते हैं।

## डेनमार्क के बैडमिंटन स्टार विक्टर एक्सेलसन ने लिया संन्यास

दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन डेनमार्क के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने बुधवार को अचानक पेशेवर खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 32 वर्षीय एक्सेलसन लंबे समय से पीठ की गंभीर चोट से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया।सूत्रों के अनुसार, एक्सेलसन पिछले वर्ष अक्टूबर से किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सके थे। पीठ दर्द की समस्या के चलते उन्होंने सर्जरी भी कराई थी और लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन से गुजरे, लेकिन इसके बावजूद दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और अक्टूबर में यह समस्या फिर से उभर आई।विक्टर एक्सेलसन ने 'बैडमिंटन यूरोप' से बातचीत में कहा कि वह काफी समय से पीठ दर्द से परेशान थे और सर्जरी के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दर्द इतना अधिक है कि वह न तो खेल पा रहे हैं और न ही अभ्यास कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक्सेलसन ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें एक और सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन इसके सफल न होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में उन्होंने अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए संन्यास लेने का निर्णय लिया।अपने करियर में विक्टर एक्सेलसन ने दो ओलंपिक (टोक्यो और पेरिस) में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा वे 2017 और 2022 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी विश्व विजेता रहे। वह 183 सप्ताह तक पुरुष एकल बैडमिंटन में विश्व नंबर-1 खिलाड़ी रहे, जो उनकी महान उपलब्धियों में शामिल है।

## आईपीएल 2026 में केकेआर का खराब प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर उठे सवाल

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का आईपीएल 2026 में अब तक का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम को टूर्नामेंट में एक भी जीत हासिल नहीं हुई है, जिसके चलते कप्तान अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं तेज हैं कि बीच टूर्नामेंट में उनसे कप्तानी छीनी जा सकती है। अब तक खेले गए मुकाबलों में केकेआर को जीत का स्वाद नहीं मिला है। टीम के खाते में सिर्फ एक अंक है, जो बारिश के कारण रद्द हुए मैच से मिला। उस मैच में भी टीम की स्थिति मजबूत नहीं थी। इसके अलावा खेले गए चारों मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।हालांकि, टीम की इस स्थिति के लिए केवल कप्तान को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अन्य खिलाड़ी भी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके क्रिकेट में हार का ठीकरा अक्सर कप्तान के सिर ही फोड़ा जाता है। पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में भी अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन औसत रहा था। 14 मैचों में केकेआर को केवल 5 जीत मिली थीं, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। टीम 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। अगर रहाणे के कप्तानी करियर की बात करें तो उन्होंने आईपीएल में अब तक 43 मैचों में टीम की अगुवाई की है, जिनमें से केवल 14 मुकाबलों में जीत मिली है। उनका जीत प्रतिशत 34.14 है, जो 30 से अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में सबसे कम में गिना जाता है। बल्लेबाजी में भी उनका प्रदर्शन खास प्रभावी नहीं रहा है। पांच मैचों में उन्होंने एक अर्धशतक और 41 रनों की पारी जरूर खेली है, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट करीब 125 रही है, जो आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिहाज से कम मानी जाती है। ऐसे में केकेआर की खराब फॉर्म और रहाणे के प्रदर्शन को देखते हुए टीम प्रबंधन आगे क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

घायल बेजुबान को पीठ पर लादकर चला शख्स

# पहाड़ों जैसा ऊंचा हौसला

दूर पहाड़ों के एक गांव से आया एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंसानियत की ऐसी झलक देखने को मिल रही है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यहां एक शख्स एक बेजुबान जानवर के साथ अपने रिश्ते को निभाता नजर आ रहा है.वीडियो में दिखता है कि एक आदमी संकरे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चढ़ाई कर रहा है. उसकी पीठ पर एक बड़ी टोकरी बंधी हुई है. उसी टोकरी में एक घायल आवारा कुत्ता बैठा है, जो अपने पैर की चोट के कारण चलने में पूरी तरह असमर्थ है. रास्ता इतना मुश्किल था कि वहां किसी भी तरह का वाहन पहुंच ही नहीं सकता था. पत्थरों से भरा रास्ता, टूटी सीढ़ियां और

खड़ी चढ़ाई.हर कदम पर चुनौती थी. लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी. वह धीरे-धीरे कुत्ते को अपनी पीठ पर लेकर ऊपर चढ़ता रहा. उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, जो उसे संभालते हुए रास्ता दिखा रहा था. बताया गया कि यह कुत्ता काफी समय से घायल हालत में वहीं पड़ा था और खुद से कुछ भी करने में असमर्थ था. ⊙

लाल शर्ट वाले युवक ने 'कांटा लगा' स्टेप्स से जीता दिल

# पेट्रोल पंप पर युवक का डांस वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप के बीचों-बीच बेफिक्र होकर डांस करता नजर आ रहा है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें युवक बिना किसी झिझक के अपने मन से डांस करता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना दिन के समय की है, जब पेट्रोल पंप पर रोज की तरह गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी. लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे और पेट्रोल भरवा रहे थे. तभी अचानक एक युवक, जो लाल शर्ट और साधारण पैंट पहने हुए था, वहां आकर डांस करने लगा.शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसका डांस काफी तेज हो

पहले भी कई लोग सार्वजनिक जगहों पर अचानक डांस करते हुए नजर आए हैं.

गया. युवक को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास कितने लोग हैं या कौन उसे देख रहा है. वह पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोकर नाच रहा था. उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है. डांस के दौरान युवक ने कई मशहूर गानों पर परफॉर्म किया. कभी वह कांटा लगा गाने पर झूमता नजर आया, तो कभी घुंघरू टूट गए जैसे गानों के स्टेप्स करता दिखा. उसके स्टेप्स में आत्मविश्वास और मस्ती दोनों साफ दिखाई दे रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े मंच पर परफॉर्म कर रहा हो, जबकि वह एक साधारण पेट्रोल पंप पर नाच रहा था. ⊙

इंटरनेट की मशहूर मुस्कान वाले लड़के की है दर्दभरी कहानी

# चाय का कप और बेफिक्र हंसी

**सोशल मीडिया पर अपनी बेफिक्र हंसी के लिए मशहूर तेलंगाना के अरूण कुमार ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास कर ली है. कभी ट्रक क्लीनर रहे अरूण को उनके साथी ड्राइवर नेहरू ने न केवल वायरल किया, बल्कि उनकी पढ़ाई पूरी कराकर जीवन बदल दिया.**

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वायरल मीम या रील के अंत में चाय का गिलास पकड़े और खिलखिलाकर हंसता एक लड़का दिखाई देता है. साधारण से दिखने वाले इस लड़के की हंसी इतनी प्रभावी है कि किसी भी रील, वीडियो या मीम के फन मोमेंट का यह आज सिंबल बन चुका है. इंटरनेट की दुनिया में हंसी और फन का सिंबल बन चुका ये वायरल लाफिंग बॉय कौन है? इस हंसी वाले मोमेंट की क्या कहानी है, जो इतना वायरल हुआ कि आज हर एक रील और मीम में दिखाई देता है. चाय का कप पकड़े, खिलखिलाकर हंसने

अरूण कुमार है इस वायरल लाफिंग बॉय का नाम (Photo - Social Media)

वाले इस लड़के का नाम अरूण कुमार है. यह तेलंगाना का रहने वाला है. इसकी स्वाभाविक और दिल खोलकर हंसने के अंदाज ने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई होगी, लेकिन लोगों को हंसाने वाले इस लड़के की खुद की कहानी काफी संघर्ष और मुश्किल भरी है. इन दिनों अरूण इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसने इस साल मार्च में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली. जिस शख्स ने कभी इसकी हंसी को कैमरे में कैदकर वायरल किया था. उस नेहरू नाम के व्यक्ति ने ही अरूण को पढ़ा-लिखाकर 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कराई है. गरीबी के कारण अरूण ने चौथी क्लास तक पढ़ने के बाद बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था. फिर उसे नेहरू नाम के एक ट्रक ड्राइवर साथ मिला. नेहरू ने अरूण को ट्रक पर क्लीनर की नौकरी दे दी. अरूण की जिंदगी नेहरू के साथ ट्रक पर दूर-दराज की यात्रा करते और हाईवे पर ट्रक के टायरों की धूल झाड़ते कटने लगी. ट्रक पर यहां-वहां जाते टाइम पास के लिए नेहरू रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता था.

एक दिन उसने नेहरू का चाय पीते हुए और किसी बात पर बेफिक्री में खिलखिलाकर हंसते हुए पल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. अरूण की ये बेफिक्र हंसी लोगों को इतनी पसंद आई कि रातोंरात नेहरू का ये वीडियो वायरल हो गया. फिर क्या था, अरूण इंटरनेट पर वायरल लाफिंग बॉय के नाम से फेमस हो गया. आज अधिकतर फनी रील और मीम्स में अरूण की हंसी वाले कुछ सेकेंड का फुटेज जरूर होता है. ⊙

## अजनबी को चलती ट्रेन के आगे धकेला

अमेरिका के सिएटल से एक बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है. मामला नॉर्थगेट लाइट रेल स्टेशन का है, जहां 19 मार्च 2026 की शाम करीब 6 बजे एक युवक ने प्लेटफॉर्म पर खड़े अजनबी को आती ट्रेन के सामने धकेलने की कोशिश की. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में साफ दिखता है कि पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होकर अपने फोन में व्यस्त था. ⊙

# 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक रिलीज, डबल ट्रबल लव स्टोरी ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। रिलीज होते ही इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है और फैंस इसकी कहानी और कॉमेडी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।फर्स्ट लुक वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प और मजेदार सीन से होती है, जिसमें दो छोटे बच्चे साथ बैठे हुए बातचीत करते दिखाई देते हैं। दोनों अपने-अपने माता-पिता के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा बताता है कि उसकी मां का नाम बानी है, जबकि दूसरा कहता है कि उसकी मां का नाम प्रीत है। इसके बाद जब दोनों अपने पिता का नाम बताते हैं, तो चौंकाने वाला मोड़ आता है—दोनों अपने पापा का नाम 'जैस' बताते हैं। इतना ही नहीं, दोनों यह भी बताते हैं कि उनके पिता की जन्मतिथि भी

एक ही दिन है। इस पर दोनों बच्चे हैरानी जताते हुए कहते हैं कि कहीं उनके पापा एक ही तो नहीं।इसके बाद वीडियो में वरुण धवन को मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाया गया है। वीडियो के अंत में बच्चे 'डबल ट्रबल लव स्टोरी' कहते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि फिल्म में कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरपूर कहानी देखने को मिलेगी। फर्स्ट लुक से यह भी संकेत मिलता है कि वरुण धवन का किरदार दो अलग-अलग महिलाओं के बीच फंसा नजर आएगा, जो फिल्म को और दिलचस्प बनाता है।इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। जाह्नवी कपूर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इन बच्चों को कौन बताएगा कि उनके पापा कितने क्रेजी हैं। वहीं मौनी रॉय और अवनीत कौर ने भी इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जो पहले भी कई हिट कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं। वहीं फिल्म को रमेश तौरानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार है, जिसमें मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, मौनी रॉय और अली असगर जैसे कलाकार शामिल हैं।फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फर्स्ट लुक के बाद से ही दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और अब सभी को इसके ट्रेलर और रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

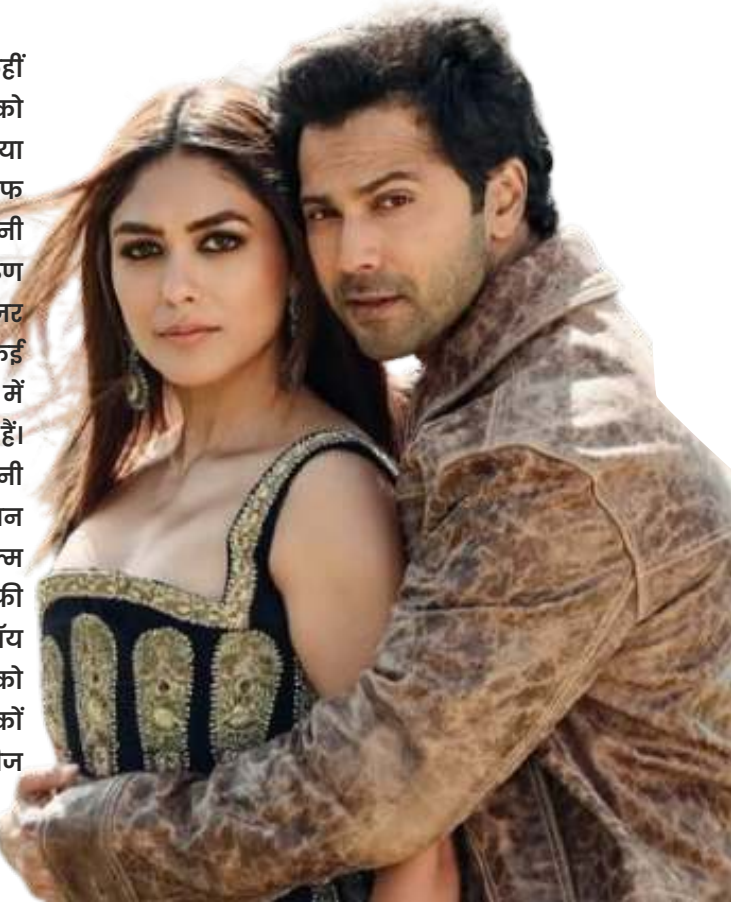

# सीएम योगी ने 10 लाखवीं ई-बस को दिखाई हरी झंडी

## यूपी बना मैन्युफैक्चरिंग हब, टाटा मोटर्स ने रचा इतिहास

**लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाख वाहनों का उत्पादन पूरा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-बस को हरी झंडी दिखाई। कंपनी ने इसे बड़ा माइलस्टोन बताया और 5 साल में 20 लाख वाहन बनाने का लक्ष्य रखा। प्लांट से 15 देशों में निर्यात होता है और हजारों को रोजगार मिला है।**

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

टाटा मोटर्स के लखनऊ स्थित प्लांट ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 10 लाख वाहनों का उत्पादन पूरा कर लिया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 10 लाखवीं गाड़ी के रूप में तैयार ई-बस को हरी झंडी दिखाई और स्वयं उसकी सवारी भी की। कार्यक्रम के दौरान एन. चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री को ई-बस की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 10 लाख वाहनों का उत्पादन केवल एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक "ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड" है। उन्होंने इसे नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बताते हुए कहा कि राज्य तेजी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने विश्वास जताया कि यह विकास की गति अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और तेज होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की 25 करोड़ आबादी में 56 प्रतिशत युवा हैं, जिन्हें कौशल, नवाचार और तकनीक से जोड़कर उद्योग के लिए तैयार किया जा रहा है। बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ने प्रदेश में औद्योगिक माहौल को नई मजबूती दी है।टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इस उपलब्धि को कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन बताते हुए कहा कि लखनऊ प्लांट में एक मजबूत सप्लायर, पार्टनर और कम्युनिटी इकोसिस्टम विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि कंपनी का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों का उत्पादन करने का है। चिनहट स्थित देवा रोड पर बना यह प्लांट वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यहां करीब 8 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस प्लांट में लाइट, हैवी कमर्शियल व्हीकल और बसों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें दुनिया के 15 देशों में निर्यात किया जाता है।टाटा मोटर्स के सीईओ और एमडी गिरीश वाघ ने कहा कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने बताया कि यह प्लांट वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में 'जीरो वेस्ट' का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जो पर्यावरण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम योगी ने टाटा समूह की सराहना करते हुए कहा कि बचपन से ही टाटा के वाहन लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं और आज भी यह नाम विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह की यूपी के साथ साझेदारी केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास और भरोसे का मजबूत आधार है। यह उपलब्धि न केवल उद्योग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए भी एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

# लखनऊ नगर निगम सदन में हंगामा, सोलर पैनल मुद्दे पर तीखी नोकझोंक

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ नगर निगम की सदन बैठक बुधवार को करीब सवा दो घंटे तक हंगामेदार माहौल में चली। सुबह 9 बजे जैसे ही बैठक शुरू हुई, सोलर पैनल पर दी जा रही छूट को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो जल्द ही तीखी बहस में बदल गई। बैठक के दौरान भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह की एक टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, "किसी को कुछ नहीं आता, चुनाव चिह्न छाता।" इस बयान पर मेयर सुषमा खर्कवाल नाराज हो गईं और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि "कोई भी मां के पेट से सीखकर नहीं आता। अगर किसी को दिक्कत है तो वह सदन छोड़ सकता है।" इस दौरान कुछ पार्षदों ने उन्हें बोलने का अवसर न मिलने का आरोप लगाया। विरोध जताते हुए भाजपा पार्षद हरिश्चंद्र लोधी, उमेश सनवाल और प्रमोद सिंह राजन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनके इस कदम से बैठक का माहौल और गरमा गया।बैठक के दौरान समय की पाबंदी को लेकर भी सख्ती देखने को मिली। देरी से पहुंचने पर मेयर ने लायन एनवायर कंपनी के मालिक रणधीर सिंह को फटकार लगाई और पूछा कि वे देर से क्यों आए। इस पर कुछ देर तक सदन में हल्की नोकझोंक भी हुईहंगामे के बावजूद सोलर पैनल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी रही, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आए। पार्षदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिससे बैठक का माहौल बार-बार बाधित हुआ।नगर निगम की यह बैठक शहर के विकास और योजनाओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन राजनीतिक तकरार के कारण कई बार कार्यवाही प्रभावित हुई।

# लखनऊ के आशियाना में एसी ब्लास्ट से लगी भीषण आग

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी के आशियाना क्षेत्र में बुधवार (15 अप्रैल) को उस समय हड़कंप मच गया, जब मोती महल रेस्टोरेंट और गीतांजलि शोरूम में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा एसी ब्लास्ट के कारण हुआ, जिसके बाद आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना के दौरान उठती ऊंची लपटों को देख आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना विवेक प्लाजा स्थित पावर हाउस चौराहे के पास की है, जहां मोती महल रेस्टोरेंट और गीतांजलि शोरूम एक ही परिसर में स्थित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शोरूम के बाहर कूड़े के ढेर में पहले आग लगी, जिसने पास में लगे एसी के आउटर यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एसी में जोरदार ब्लास्ट हुआ और आग तेजी से फैल गईबताया जा रहा है कि आग की शुरुआत रेस्टोरेंट के किचन के पास से हुई और देखते ही देखते लपटें फैलकर शोरूम तक पहुंच गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र धुएं और आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाद में दो और गाड़ियां बुलाई गईं। कुल चार दमकल गाड़ियों की मदद से करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के

हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, आग से रेस्टोरेंट और शोरूम को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर एसी ब्लास्ट को आग फैलने का मुख्य कारण माना जा रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा और लोगों में दहशत देखी गईप्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते बड़ी घटनाओं को टाला जा सके।

# लखनऊ में बढ़ी गर्मी, पारा 40 डिग्री के करीब

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी लखनऊ में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि दिन में तेज पछुआ हवाएं चलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम रहा। वहीं, अधिकतम आर्द्रता 55 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 22 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। इसके बावजूद पिछले चार दिनों में तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश भर में गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है।उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा जिले में 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवाओं की रफ्तार में कमी आने से तापमान में 2-3 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, आने वाले 4-5 दिनों तक किसी सक्रिय मौसम प्रणाली के संकेत नहीं हैं, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। उन्होंने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं, वर्ष 2026 के मानसून को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। प्रशांत महासागर में ला-नीना की कमजोर स्थिति के समाप्त होने और अल-नीनो जैसी परिस्थितियों के बनने की आशंका है, जिससे बारिश कम हो सकती है।यदि मानसून कमजोर रहता है, तो इसका असर खेती और जल संसाधनों पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

# रहीमाबाद में अनियंत्रित ट्रक मकान में घुसा, बड़ा हादसा टला

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के अनीपुर गांव में बुधवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। इस हादसे में मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, केसरीपुर निवासी ट्रक चालक सराफत सस्पन की ओर से रहीमाबाद की तरफ जा रहा था। अनीपुर गांव के पास पहुंचते ही चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे महेंद्र उर्फ टीटू के घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान की दीवारें ढह गईं और घर में रखा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। घटना के समय घर के सदस्य उस हिस्से में मौजूद नहीं थे, जहां ट्रक घुसा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उस समय कोई व्यक्ति वहां होता, तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने ट्रक चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।सूचना मिलते ही रहीमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है।

# लखनऊ मेट्रो फेज-2 को 2883 करोड़ की फंडिंग, एनडीबी ने दी मंजूरी

राजधानी लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना को बड़ा वित्तीय सहारा मिल गया है। चारबाग से बसंतकुंज तक बनने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-2) के लिए ब्रिक्स देशों के बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने लोन देने पर सहमति दे दी है। यह बैंक परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत यानी 2883.93 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5801.05 करोड़ रुपये है। इसमें शेष आधी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। दोनों सरकारें 1446.96-1446.96 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लोन से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है, जिसमें लगभग डेढ़ से दो महीने का समय लग सकता है। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर मेट्रो परियोजनाओं के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण लिया गया था, लेकिन अधिक ब्याज दरों के चलते अब एनडीबी से वित्तीय सहायता ली जा रही है।लोन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले चरण में पांच एलिवेटेड स्टेशनों और ठाकुरगंज से बसंतकुंज तक करीब 4.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वायडक्ट का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसमें डिपो को जोड़ने के लिए रैंप निर्माण भी

शामिल होगा। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 11.16 किलोमीटर होगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से पांच स्टेशन एलिवेटेड और सात स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। अंडरग्राउंड स्टेशनों में नवाबगंज, मेडिकल चौराहा, सिटी रेलवे स्टेशन, पांडेयगंज, अमीनाबाद, गौतमबुद्ध मार्ग और चारबाग शामिल हैं। इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र चारबाग स्टेशन होगा, जिसे इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां यात्रियों को नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (मुंशीपुलिया-एयरपोर्ट) से कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों को ईस्ट-वेस्ट रूट से एयरपोर्ट या मुंशीपुलिया जाने के लिए चारबाग पर मेट्रो बदलनी होगी। यह परियोजना पूरी होने के बाद लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा शहर के प्रमुख क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

# डीएम की फटकार के बाद हुई कार्रवाई

## फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर पर 7 महीने बाद एफआईआर

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए फर्जी डिग्री लगाने वाले डॉक्टर के खिलाफ डीएम के आदेश के सात महीने बाद प्राथमिकी दर्ज हुई है। विभागीय अफसर लंबे समय तक मामले को दबाने में लगे रहे। सोमवार को हुई बैठक में जब डीएम को फिर इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद सेंटर संचालक की तहरीर पर डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गईनगर पंचायत क्षेत्र में संचालित अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक, कोतवाली क्षेत्र के बगहा गांव निवासी अंशु पटेल ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि सेंटर में अल्ट्रासाउंड संचालन के पंजीकरण के लिए वाराणसी जिले के लंका क्षेत्र निवासी खेसारी रमनलाल ने एमबीबीएस और डीएमआरडी की डिग्रियों के दस्तावेज जमा किए थे। जब इन प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन जांच की गई, तो वे फर्जी पाए गए।गौरतलब है कि डॉक्टर ने करीब सात महीने पहले स्वास्थ्य विभाग में आवेदन किया था। 9 सितंबर 2025 को पीसीपीएनडीटी की बैठक में डीएम ने अभिलेख फर्जी पाए जाने पर जांच सीएमओ को सौंपी थी। 15 सितंबर 2025 को डिग्री फर्जी मिलने की पुष्टि हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को दबाए रखा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।सोमवार को हुई अगली पीसीपीएनडीटी बैठक में जब डीएम को पता चला कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम के सख्त रुख के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक पर दबाव बनाया और बीघापुर कोतवाली में तहरीर दिलवाकर प्राथमिकी दर्ज कराई।कोतवाल राजपाल के अनुसार, सेंटर संचालक की शिकायत पर खेसारी रमनलाल के खिलाफ कूटरचित अभिलेख तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी इंदामऊ चौकी प्रभारी राजेश सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है और संबंधित संस्थानों से भी सत्यापन कराया जा रहा है।यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि समय रहते कार्रवाई होती तो इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आती। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री के सहारे कमाई करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले हसनगंज में भी एक डॉक्टर के खिलाफ पीसीपीएनडीटी प्रभारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वर्तमान में तीन अन्य डॉक्टर भी विभाग के रडार पर हैं, जिनकी जांच जारी है। 8 अप्रैल को हसनगंज कोतवाली में डॉ. राजविजय सिंह के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था। सीएमओ सत्यप्रकाश ने बताया कि जांच प्रक्रिया जारी है और जल्द ही अन्य दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

## चौंकाने वाला मामला:युवक का शव कब्र से गायब

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरधरपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दफनाए गए एक युवक का शव लगभग एक माह बाद कब्र से गायब मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की बहन ने इसे हत्या बताते हुए उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, सिरधरपुर निवासी 20 वर्षीय हिमांशु पाल पुत्र रामबरन कानपुर के कल्याणपुर में मोमोज का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था। बीते 9 मार्च को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद 10 मार्च को शव को गांव लाकर गंगा तट के किनारे दफना दिया गया था। हाल ही में गांव में एक अन्य व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के पिता की नजर अपने बेटे की कब्र पर पड़ी। उन्हें कुछ असामान्य लगा, क्योंकि कब्र के ऊपर वही कपड़ा पड़ा था जिसमें शव को लपेटा गया था। शक होने पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और कब्र की खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान जो सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। कब्र के अंदर शव मौजूद ही नहीं था। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। यह मामला सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

## नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

## 17 मदर-न्यू बॉर्न केयर यूनिट का लोकार्पण

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 17 मदर एवं न्यू बॉर्न केयर यूनिट (एमएनसीयू) का लोकार्पण किया गया। मुख्य कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचलगंज में आयोजित हुआ। इसमें सांसद साक्षी महाराज, विधायक आशुतोष शुक्ल, जिलाधिकारी गौरांग राठी और मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज मौजूद रहे। इन एमएनसीयू यूनिट्स को अचलगंज सहित जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी स्थापित किया गया है। यह व्यवस्था 'जीरो सेपरेशन केयर' सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु को अलग नहीं किया जाता, बल्कि एक साथ रखकर उनकी देखभाल की जाती है। इससे नवजात के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मां को भी बेहतर सुविधा मिलती है। अधिकारियों ने बताया कि इन यूनिट्स से कंगारू मदर केयर को बढ़ावा मिलेगा। यह कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे बच्चों की विशेष देखभाल में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, यह व्यवस्था स्तनपान को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जनप्रतिनिधियों ने इन यूनिट्स का उद्घाटन किया। गंगाघाट में विधायक पंकज गुप्ता, औरास में विधायक बृजेश रावत, मियागंज में विधायक बम्बालाल दिवाकर और बांगरमऊ में विधायक श्रीकांत कटियार के प्रतिनिधि ने यूनिट का शुभारंभ किया। पुरवा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह पहल जनपद में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एमएनसीयू यूनिट की स्थापना से अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज और देखभाल उपलब्ध हो सकेगी, जिससे लोगों को बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## कालूखेड़ा कांथा मार्ग की मरम्मत: दो करोड़ से पांच माह में होगी

कालूखेड़ा-कांथा मुसन्ना मार्ग के किलोमीटर नंबर तीन, चार, पांच, सात, नौ और 12 की हालत जर्जर है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। गड्ढों में वाहन फंसने से अक्सर जाम लग जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रांतीयखंड के अधिकारियों ने सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण कराने का दो करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। शासन ने इसे मंजूरी देते हुए बजट स्वीकृत कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक तरफ लखनऊ तो दूसरी ओर रायबरेली को जोड़ता है मार्ग। यह मार्ग एक तरफ लखनऊ तो दूसरी ओर रायबरेली को जोड़ता है। इस मार्ग पर विभिन्न कंपनियों ने अपने गोदाम बना लिए हैं। ऐसे में भारी वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। इससे अक्सर मार्ग पर जाम लगता है। मार्ग सही होने से करीब 50 हजार की आबादी को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। कालूखेड़ा-कांथा-मुसन्ना मार्ग क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत कराई जानी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काम पूरा करने की समय सीमा पांच माह तय की गई है। टेंडर के बाद काम शुरू कराया जाएगा। -हरदयाल अहिरवार, अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीयखंड।

# नोएडा में औद्योगिक शांति को लेकर सख्ती

## उपद्रव पर एजेंसियों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

**नोएडा में हाल ही में मजदूरों के प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है।जिलाधिकारी मेधा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए।श्रमिकों के वेतन, अधिकारों और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन या उपद्रव की स्थिति में एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।**

नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को प्रशासन ने सख्ती से लिया है। जिले में औद्योगिक शांति बनाए रखने और शासन की गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री को चलाने तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन सभी की जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों के हितों का भी ख्याल रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी या उसके कर्मचारी के द्वारा उपद्रवी व्यवहार किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की भी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने न्यूनतम वेतन का उल्लेख करते हुए बताया कि अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये प्रतिमाह वेतन तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को पूरा वेतन सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाए। किसी भी प्रकार का शोषण या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, श्रमिक एवं नियोजक तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। उद्योगों का सुचारू संचालन रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रखता है, वहीं नियोजकों की स्थिरता से श्रमिकों का भविष्य भी सुनिश्चित होता है। यदि औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सभी पक्षों के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास पर पड़ता है। उन्होंने सभी से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए आपसी सहयोग एवं विश्वास के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी ने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार श्रमिकों एवं नियोजकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और किसी भी समस्या के समाधान हेतु प्रशासन तत्परता से कार्य करेगा।lvउन्होंने एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया और कहा कि सीएम के निर्देश पर हाईपावर्ड कमिटी का गठन किया गया और श्रमिकों की मुख्य मांग को मानते हुए वेतन बढ़ाया गया है। उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की साथ ही उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अतुल कुमार, डीडी फैक्ट्री बृजेश, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद रहे।

## मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण बिल ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) में संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आधी आबादी को बराबरी पर लाने का काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। हालांकि, मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं को आज की राजनीति से दूर रहने का मशवरा दिया है। मौलाना रजवी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अधिक महिलाएं चुनकर संसद पहुंचें। उनका मानना है कि इससे महिलाओं का नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। मौलाना ने बताया कि उनसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम महिलाएं सवाल कर रही हैं। वे जानना चाहती हैं कि मुस्लिम महिलाओं का सियासत में जाना कैसा है। इस पर उन्होंने अपनी मुस्लिम बहनों को बताया कि कल की सियासत और आज की सियासत में जमीन-आसमान का फर्क है। आज की सियासत छल-कपट का जाल है। यह दलदल जमीन की तरह है। सियासी मैदान में महिलाओं को इज्जत, सम्मान और विकार नहीं मिल सकता। इसके साथ ही बेपर्दगी भी होगी। मौलाना ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को घर की जीनत करार दिया है। उनकी रक्षा, सुरक्षा और सम्मान के नजरिए से इस्लाम इस तरह की सियासत से रोकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं को आज की सियासत से दूर रहना चाहिए।

## फ्लाईओवर बनेगा नया अर्बन हॉटस्पॉट सजेगा आधुनिक जोन

जिला प्रशासन ने विकास की दिशा को नई गति देने के लिए तरना फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थान को आधुनिक और आकर्षक रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। एयरपोर्ट जाने और आने वाले इस रास्ते पर अब एक आधुनिक गेमिंग और वेंडिंग जोन तैयार किया जाएगा, जिससे काशी के लोगों को बेहतर मनोरंजन सुविधा मिलेगी। वहीं, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रस्तावित इस गेमिंग जोन को बच्चों व युवाओं की जरूर को ध्यान में रखते हुए यहां निर्मित किया जा रहा है। यहां बैडमिंटन कोर्ट, पीकल बॉल और स्केटिंग जैसे खेल के कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल के कारण खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चे वा युवा सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में खेल सकेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए और स्थान की समस्या को दूर करने में यह कोर्ट निर्णायक साबित होगा।उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे ही वेंडिंग जोन भी बनाया जाएगा, जहां छोटे बड़े व्यापारी अपनी दुकान लगा सकेंगे और इससे स्ट्रीट वेंडर्स को भी काफी फायदा पहुंचेगा। यहां आने वाले लोग इस वेंडिंग जोन में कई प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही यह वेंडिंग जोन आजीविका का एक मुख्य साधन के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। उन्होंने बताया कि यहां एक पार्किंग की व्यवस्था भी करने की योजना है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इससे ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे का स्थान अक्सर खाली रह जाता है और ऐसी परियोजनाओं के जरिए इन्हें उपयोगी बनाकर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह पहल शहरी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही समावेशी, विकास, रोजगार सृजन और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

## लिसकर्मियों को भी नियमों के खिलाफ अतिरिक्त वेतन जारी कर दिया

यूपी के कानपुर पुलिस विभाग में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 48 पुलिसकर्मियों को नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त वेतन दिए गया। हालांकि, अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। इस केस में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल, पुलिस विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले एक महीने के अतिरिक्त वेतन में गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि लंबी छुट्टी पर गए 48 पुलिसकर्मियों को भी नियमों के खिलाफ अतिरिक्त वेतन जारी कर दिया गया था। मामला सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से दिए गए वेतन की वसूली कर ली है। साथ ही, इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। कार्रवाई के तहत एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और दो ASI रैंक के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें आगे और कार्रवाई संभव है। इस मामले पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम एवं हेडक्वार्टर) संकल्प शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को ड्यूटी करने के एवज में एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। नियम यह है कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस अवधि में अवकाश लेता है तो उतने दिनों के मानदेय में कटौती कर दी जाती है। लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष के दौरान कई पुलिसकर्मियों के अवकाश वाले दिनों की कटौती नहीं की गई और उन्हें पूरा अतिरिक्त मानदेय दे दिया गया।